

ग्रसाबारस

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3----उपखण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ŕ• 426]

नई दिल्ली, श्वनिवार, सितम्बर 23, 1972/ग्रादिवन 1, 1894

No. 426; NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972 ASVINA 1, 1894

इस भाग में मिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 23rd September 1972

S.O. 622(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for securing the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike or lockout in the works connected with the IDIKKI Hydro-electric project in the State of Kerala would prejudicially affect the defence of India and for maintaining supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said works:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, strike or lockout, in connection with any industrial dispute, in the said works for a period of six months.

[No. F.S.42025/1/72-LR.I.]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

श्रम ग्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रीर रोजनार विभाग)

प्रादेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1972

का ० था ० 622(ध्र).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में भारत की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये समुदाय के जीवन के लिये श्रावश्यक प्रदाय धाँर सेवाए बनाए रखने के लिये ऐसा करना श्रावश्यक श्रौर समीचीन है;

श्रीर यतः केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत् प्रायोजना से सम्बन्धित किसी कार्य में कोई हड़ताल या तालाबन्दी भारत की रक्षा पर श्रीर समुदाय के जीवन के लिये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त सेवा में हड़ताल को रोकना शावश्यक श्रीर समीचीन है।

श्रतः, श्रव, भारतं सरकार रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सेवा में किसी भी श्रीद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हुक्ताल या तालाबन्दी को तुरन्त से छः मारा की श्रवधि के लिये प्रतिपिद्ध करती है।

[सं ० फा ० एस- 42025/1/72-एल ० श्वार०-I]

नि०प्र० दुबे, ग्रपर सचिव।